Power generating equipments by BHEL

558. SHRI B. SATYANARAYAN REDDY: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that indiscriminate import of generators by the Station Power Boards seriously affecting the production of the generating equipment by Bharat Heavy Electricals Limited;

(b) if so, whether Government propose to curb such liberal imports of machinery by the power boards of States; and

(c) if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (PROF. K. K. TEWARY): (a) to (c) It is Government's Policy to ensure Maximum utilisation of the indigenous capacity. Import is resorted to only selectively depending on the totality of circumstances.

सरकारी क्षेत्र के उद्यम

559. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 20 जनवरी, 1987 को अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक उद्यम कांग्रेस में प्रधानमंत्री द्वारा की गई इस घोषणा को कार्यान्वित किये जाने के सिलसिले में कितनी वास्तविक प्रगति हुई है कि सरकार चाहती है कि सरकारी क्षेत्र दुरुस्त, और लाभकारी हो तथा वह सामाजिक दायित्व को पूरा करे और इसके कार्यकरण में आपस में अधिक स्वतंत्रता तथा तालमेल हो ;

(ख) क्या इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से संचालन – कुशलता व्यवस्था के संतुलन तथा श्रामिक व्यवस्था में कोई सुधार हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो सार्वजनिक उद्यमों क लाभहानि तथा आय की समीक्षा का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में लोक उद्यम विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) से (ग) प्रधान मंत्री महोदय ने अपने उद्घाटन भाषण में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में बेहतर प्रचालन संबंधी कार्य-कुशलता प्राप्त करने, उपलब्ध मानवीय एवं वित्तीय दोनों संसाधनों के बेहतर प्रबन्ध तथा ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण की महत्ता पर बिशेष बल दिया था । प्रधान मंत्री महोदय ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उनका भी हवाला दिया था यह बताया था कि उनकी समस्याओं को हल करने में अधिकाधिक व्यावसायिक एवं गतिशील पद्धति अपनाने की आवश्यकता है । उन्होंने अधिकाधिक स्वायत्तता एवं संबद्ध जवाब-देही की आवश्यकता पर भी बल दिया था। किन्तु कोई नई नीति संबंधी निर्देश घोषित नहीं किये गये थे।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उत्पादन एवं लाभकारिता में वृद्धि करने के लिए सरकार एवं सरकारी क्षेत्र के उपक्रम विभिन्न उपाय करते रहे हैं । इनमें से कुछ उपाय हैं संयंत्र एवं उपस्कर का, जहां कहीं आवश्यक समझा गया, आधुनिकीकरण एवं पुनर्स्थापन करना, उत्पादन -मिश्र का विविधीकरण करना, संतोलक सुविधाओं की व्यवस्था करना, कार्मिकों को प्रशिक्षण एवं पुनप्रशिक्षण दिलाना, लागत नियंत्रण एवं लागत घटाने पर जोर देना और प्रबन्ध में श्रमिक भागीदार को प्रोत्साहन देना । सरकारी उद्यमों के प्रबन्धकों को अधिकाधिक स्वायत्तता प्रदान करने के भी उपाय किये गये हैं । इन उपायों के अच्छे परिणाम दिखलाई पड़े हैं जिन्हें लोक उद्यम सर्वेक्षण 1985–86 में देखा जा सकता है, जिसे 27 फरवरी, 1987 को सभा-पटल पर रखा गया है।

Pending cases in High Courts

560. SHRI T.R. BALU:
SHRI V. GOPALSAMY:

Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state:

(a) the total number of Civil and Criminal cases which are pending for disposal in each High Court as on date?